POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2024/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

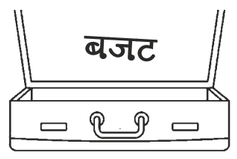

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अगस्त, 2024 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्य विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तमंत्री के रूप में मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट रखा। यह भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट है। बजट में 'पहला सुख निरोगी काया' पर खास फोकस है।

बजट में पांच साल में युवाओं को चार लाख नौकरियां व दस लाख को रोजगार देने, बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क टेबलेट बांटने, खेती व किसानी को लाभप्रद बनाने, महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने, हर परिवार को घर के लिए अनुदान देने और शहरों से ग्रामीण स्तर तक बुनियादी ढांचे को मजबूती देने जैसी कई घोषणाएं कर सभी को 'गदगद' करने का प्रयास है।

खास यह है, बजट में वर्ष 2047 का लक्ष्य तय करते हुए राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का विजन भी दिखाया गया है। हमारी सरकारें बहुत सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाती हैं, जो आमजन और देश के विकास में 'मील का पत्थर' साबित हो सकती हैं। लेकिन सही क्रियान्वयन एवं उचित निगरानी नहीं होने से कई सार्थक योजनाओं का बीच में ही दम टूटने लगता है। कुछ ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाएं अपने मकसद को पूरा करने में खरी साबित हों। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है।

हमारी निवेश नीति सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। प्रदेश में आए निवेशकों को निराश नहीं किया जाना चाहिए। मजबूत निगरानी व्यवस्था, कौशल विकास में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी समग्र रणनीति से मजबूत निवेश वातावरण बनेगा। जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान विकसित राज्य बन पाएगा।

मेरा मानना है कि लघु उद्यमिता और निर्यात को बढ़ावा देकर अपेक्षित लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था राष्ट्रीय आय में 46 फीसदी महत्वपूर्ण योगदान देती है। देश के सतत् विकास के लिए ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता और रोजगार आवश्यक है।

बनेगा ई-हेल्थ रिकॉर्ड, मिलेगी अत्याधुनिक चिकित्सा

प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य के लिए यह अब तक का सर्वाधिक बजट है। बजट में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की सौगात दी गई है। इसके तहत ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा और मरीज व अस्पताल का पूरा डेटा ऑनलाइन रहेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ग्रामीण स्तर तक सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 15000 करोड़ रुपए प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं पर तीन साल में खर्च किए जाएंगे।

अस्पतालों में ट्रोमा केयर पर भी खास ध्यान दिया गया है। बजट में 1500 डॉक्टरों और 4 हजार नर्सों के पद स्वीकृत किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। माताओं एवं शिशुओं के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां) लागू की गई है। इसके तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत दी गई है। इसके साथ ही शिशु व छोटे बच्चों के इलाज के लिए भी पैकेज में पीडियाट्रिक आयुष्मान योजना पैकेज जोड़ने की भी घोषणा की गई है। इससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। जेके लोन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स बनेगा। बजट में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

आयुष्मान मॉडल सीएचसी में मोर्चरी का निर्माण होगा। एसएमएस आईपीडी टावर पर चिकित्सा सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। आरयूएचएस में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज, नए अस्पताल बनाने और कई अस्पतालों को क्रमोन्नत करने जैसे कई प्रावधान भी बजट में रखे गए हैं।

निगरानी

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

कृषि क्षेत्र: किसान होंगे लाभान्वित

बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने खेती और किसानों के फायदे के लिए कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर 650 करोड़ रुपए की राजस्थान कृषि विकास योजना का गठन होगा। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का प्रावधान बजट में किया गया है। इससे प्रदेश के 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों को 100 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन कृषि ऋण भी दिए जाएंगे। कृषि ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

कृषि विद्युत कनेक्शन की लंबित पेंडेंसी खत्म होगी और इस साल एक लाख 45 हजार नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे। किसानों को 'श्री अन्न' अर्थात मोटे अनाज के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में जैविक एवं परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड गठित होगा। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिलों में यूनिट व लैब की भी स्थापना होगी। मंडियों का विस्तार होगा और नवीन कृषि मंडी यार्ड बनाए जाएंगे।

किसानों को मार्केटिंग में सशक्त बनाने के लिए 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) बनेंगे। मनरेगा के तहत मेडबंदी और पौधारोपण पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को तकनीकी यंत्रों के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा भी किसानों को बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

महिलाएं होंगी आर्थिक रूप से सशक्त

बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए है। पूर्ण बजट में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा एक अच्छा कदम है। पहले अंतरिम बजट में यह संख्या पांच लाख थी। मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक ब्लॉक में आदर्श आंगनबाड़ी विकसित कर उनमें सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है।

बजट में 300 करोड़ रुपए से 40 हजार नये स्वयं सहायता समूहों के गठन की घोषणा भी की गई है। स्वयं सहायता समूहों को 2.5 प्रतिशत की दर पर सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । देश के हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड और सार्वजनिक स्थलों, महिला छात्रावासों में व नारी निकेतनों में सीसीटीवी केमरे लगेंगे, इससे महिलाओं की सुरक्षा को बल मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बालिका के जन्म पर एक लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में होस्टल, पेइंग गेस्ट सुविधा के लिए बजट में 35 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। सेना पुलिस भर्ती के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोलने से महिलाएं लाभान्वित होगी।

गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व जांच के लिए वाउचर दिए जाएंगे। एससी-एसटी के विकास के लिए भी 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महिलाओं को सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करने के लिए बजट में कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं।

शिक्षा व रोजगार के लिए बड़ी सौगात

भजनलाल सरकार के बजट में शिक्षा, कौशल और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं के लिए स्किल डवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सरकार ने युवा नीति-2024 बनाने की घोषणा की है। इस नीति के तहत निजी सेक्टर की नौकरियों पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत निजी व सरकारी क्षेत्र में स्किल अपग्रेशन के साथ ही 10 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी जाएगी।

बजट में युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने पर भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए अटल इनोवेशन स्टूडियों और एक्सेलेरेटर स्थापित होंगे। तकनीकी शिक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से 30 नए आइटीआई बनेंगे साथ ही 150 आइटीआई विकसित होंगे। प्रदेश में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित होंगे। इसके लिए बजट में 300 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। 100 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनेगा, जो स्टार्टअप को वित्तीय सपोर्ट देगा। स्टार्टअप स्थापित करने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होंगे। रोजगार के लिए युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करवाए जाएंगे।

स्कूल-कॉलेजों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे। नये कृषि और महिला कॉलेज खोले जाने की घोषणा भी बजट में है। नए स्कूल भी खुलेंगे और पुराने क्रमोन्नत किए जाएंगे। उद्यमिता एवं कौशल शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह बेरोजगारी की समस्या से निपटने में भी सहायक हो सकेंगे।

बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान

प्रदेश के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। प्रदेश की विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना बनाई गई है। वर्ष 2032 तक परंपरागत स्रोतों से 20 हजार 500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33 हजार 600 मेगावाट क्षमता का उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। बजट में अगले दो साल में 2 लाख 8 हजार से अधिक घरों को विद्युत कनेक्शन देने और 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में आदर्श सौर ग्राम बनेंगे।

जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के 5846 गांवों में 20370 करोड़ रुपए की लागत से छह पेयजल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अगले दो साल में पेयजल व्यवस्था पर 183 शहरों और कस्बों में 5180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी जल स्रोतों का जीर्णोद्धार भी होगा जिस पर 127 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है।

शहर से लेकर गांवों तक सड़कों का जाल बिछेगा। पांच सालों में 60 हजार करोड़ रुपए से 53 हजार किलो मीटर लम्बाई का सड़क नेटवर्क बनेगा। क्षतिग्रस्त 1343 सड़कों व पुलियाओं पर दो साल में 644 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2750 किमी के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। गांवों में नई सड़कों का निर्माण होगा।

बजट में सड़क सुरक्षा व दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं, शहरों के निकायों और पंचायतों को सुदृढ़ करने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। वहीं गरीबों के लिए सस्ते आवास बनाने हेतु अनुदान के लिए पर्याप्त धन राशि स्वीकृत की गई है। शहरी आवास योजना में लाभार्थियों को 25 हजार रुपए की राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता देगी।

औद्योगिक प्रोत्साहन से बढ़ेगा निवेश

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में औद्योगिक विकास को खास महत्व दिया है। बजट में आठ इंडस्ट्रियल एरिया-पार्क और नौ नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने की घोषणा की गई है। जयपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना होगी। प्रदेश औद्योगिक हब की तरफ बढ़ेगा। छह नई पॉलिसी बनने से बड़ी कंपनियां प्रदेश में आएगी। राजस्थान का हर जिला एक्सपोर्ट हब बनेगा। इससे औद्योगिक निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

बजट में रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर 175 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान रखा गया है। जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल शुरू करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे इसमें वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडक्ट पॉलिसी लागू होगी। नई पॉलिसी एमएसएमई को बढ़ावा देने वाला कदम है।

नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अटल उद्यमी योजना बनाने का प्रावधान भी बजट में है। नए प्रोडक्ट के लिए बालोतरा में राजस्थान का पहला पेट्रो जोन बनेगा। इनके अलावा भी सरकार ने औद्योगिक विकास को पंख लगाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है।

बजट की अन्य राहतभरी खास घोषणाएं

- बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। इस नीति के तहत श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी। इससे प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे। बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। ऊंट के लिए एक लाख का बीमा होगा। इसके अलावा भेड़ बकरियों का भी बीमा होगा। इससे किसानों व पशुपालकों को अच्छा लाभ मिलेगा।
- बजट में कमजोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एससी-एसटी विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना बनेगी। गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए बजट में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्प संख्यक विकास निगम आदि को 100 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान बजट में है।
- आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए 36 लाख बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की भी बजट में घोषणा की गई है। इस वर्ष जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए 250 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू होगी। इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- जल संचय एवं संरक्षण के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485